SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Another thing I would like to know is whether the eye-witness have been examined at all in this case. So, far nothing has been said in this regard. With regard to the investigation, so many columns have been written in the papers. How far this is going on and whether the investigation is going on rightly is the question. Our Home Minister has said so many things. I am only putting all these very important aspects before him for his consideration. That is why I said certain unravelled mysteries are there and these points should be investigated in the best interest of the case.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने आपसे अनुरोध किया था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is not zero hour. We are taking up only listed Special Mentions. Were you permitted by the Chair?

श्री ईश दत्त यादव : चेयर से परमिशन तो नहीं मिली थी लेकिन . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : फिर कैसे ?

श्री ईश दत्त यादव : पीठासीन अधिकारी श्री बेबी थे। उनसे मैंने अनुरोध किया था तो उन्होंने कहा कि स्पेशल मेंशन के बाद आपको समय दे दिया जाएगा लेकिन उस समय लंच हो गया फिर प्राइवेट मैम्बर्ज का समय था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The House is meeting on Monday.

श्री ईश दत्त यादव : गृह मंत्री जी बैठे हैं, मामला गम्भीर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : गृह मंत्री जी लीडर हैं हाऊस के। वे आपको सुनेंगे।

Clarifications on the Statement regarding drought situation in the country

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में बारिश की कमी के कारण जो कृषि की हालत है उसके बारे में मंत्री जी का जो बयान आया उस के संबंध में मैं उनसे कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहती हूं। इन्होंने पेज नम्बर 2 में पैरा 8 और 9 में कुछ बातें कही हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कितनी बारिश हुई है और कितनी धान की खेती हो सकी है। पैरा नम्बर 9 में उन्होंने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इसका मुकाबला करने के लिए क्या कुछ करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि बिहार में 51,73,000 हैक्टेयर जमीन में धान की खेती होती है। गेहूं की खेती 18,73,000 हैक्टेयर जमीन में होती है। 8,74,000 हेक्टेयर में दूसरी रबी की खेती होती है तथा दूसरे सीरियल 1,60,000 हेक्टेयर जमीन में होते हैं। आप यह देखेंगे कि पिछले साल इसी समय जुलाई के अंत में और अगस्त के शुरू में 36 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हो चुकी थी और इस साल अभी तक केवल 11 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है। बिहार के 39 जिले हैं जहां धान की खेती होती है। इसके साथ एक बात और है। एक तो बारिश नहीं हुई और दूसरे एग्रोर्ड इरीगेशन जहां से उपलब्ध है जैसे सोन केनाल सिस्टम जो 117 साल पुराना है जहां से सेंट्रल बिहार के सभी स्थानों पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है वहां पानी की भी कमी हो गई है। बाणसागर एग्रीमेंट 1973 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में हुआ था जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन होगा और कम से कम पांच हजार क्युसेक पानी रिहान और सोन से बिहार को पानी मिलेगा। लेकिन अब सिंगरौली में भी बिजली का कारखाना बैठ गया है। वहां विद्युत उत्पादन के लिये पानी तो दिया जा रहा है और शहर में भी पीने के पानी और अन्य कारणों में उसका इस्तेमाल

[श्रीमति कमला सिन्हा)

हो रहा है । नतीजा यह है कि बिहार को सोन कैनाल सिस्टम में पानी नहीं मिल रहा है । सोन कैनाल सिस्टम सूख रहा है । सारे सेंट्रल बिहार के खेतों में पानी नहीं है । एक तो यह स्थिति हो गयी है । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार तत्काल सोन कैनाल सिस्टम को बाणसागर योजना के एग्रीमेंट के मुताबिक न्यूनतम साढ़े पांच हजार क्यूसेक्स पानी उपलब्ध करायेगी ? नहीं तो मध्य बिहार में जहां सोन नहर से सिंचाई होती है जिसे अनाज का भंडार कहा जा सकता है, यहां सरप्लस उत्पादन होता है, यहां भी अगर खेती मारी गयी तो फिर बिहार में हाहाकार मच जायेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं । आपने कहा है :

"..steps for creating an awareness among farmers for taking up alternate crops. Steps have been taken to ensure uninterrupted supply of power.."

यह बिहार के बारे में आपने कहा है "अनइंटरप्टेड सप्लाई आफ पावर किसानों को दिया जायेगा ।" मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहती हूं कि बिहार की टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी साढ़े 13 सौ मेगावाट है और जनरेशन होता है 3-4 सौ मेगावाट । आधे कल कारखाने बन्द पड़े रहते हैं । दामोदर वैली कारपोरेशन के जो बिजली के कारखाने हैं वहां से हमको बिजली मिल नहीं पाती है । यह स्थिति है । सभी गांवों में बिजली भी उपलब्ध नहीं है । बिजली की लाइन अभी तक नहीं जा पाई है । तो कैसे काम हो पायेगा । क्या इसके लिये आप आल्टरनेट अरैंजमेंट के रूप में डीजल को उपलब्ध करायेंगे, क्या पर्याप्त मात्रा में डीजल की उपलब्धि होगी ?

तीसरा प्रश्न मेरा बिहार के मुताबिक यह है कि सोन नहर सिस्टम से उत्तर प्रदेश और सिंगरौली में जो बिजली उपलब्ध होती है उसमें से क्या बिहार को 15 सौ मेगावाट बिजली तत्काल दी जायेगी ।

ये तो मैंने बिहार के संबंध में प्रश्न पूछे हैं । अब मैं कुछ प्रश्न वेस्टर्न यू०पी० और हरियाणा के बारे में पूछना चाहूंगी जिनके बारे में मंत्री महोदय को अच्छी तरह से जानकारी होगी । गन्ने की फसल की खेती वहां ज्यादा होती है । पानी की कमी के कारण गन्ने की खेती सूख रही है जो थोड़ी बहुत बची भी है उसमें कीड़े लग रहे हैं । क्या सरकार इस पर एरियल स्प्रे करायेगी और सस्ते दामों पर किसानों को कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करायेंगी ?

दूसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के मुताल्लिक है । धान की रोपाई लगभग 40 प्रतिशत हो पाई है । इसलिये क्या आल्टरनेट खेती के रूप में कपास और गन्ने की खेती पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देकर इनको लगवायेगी ?

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि फसल की पैदावार कम होने से किसान को होने वाले नुक्सान की भरपाई सरकार कैसे करेगी । कम से कम सिंचाई दरों में और भू-राजस्व आदि में छूट देने का विचार क्या सरकार कर रही है और क्या कम से कम इस वर्ष उर्वरक और कीटनाशक सभी दवाइयों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ?

चौथा प्रश्न यह है कि बारिश की कमी के कारण वाटर टेबुल नीचे चला गया है । वाटर टेबुल नीचे जाने के कारण लिफ्ट इरीगेशन नहीं हो पा रही है । इस स्थिति में लिफ्ट इरीगेशन के लिये डीप बोरिंग करके ट्यबवेल्स लगाने का प्रस्ताव क्या सरकार रखती है ? क्या तुरन्त इस काम को करायेगी ? धन्यवाद ।

श्री छोटू भाई पटेल (गुजरात) : वाइस चेयरमैन महोदय, आपके माध्यम से मैं सिर्फ दो तीन छोटी सी बातें

पूछना चाहूंगा । ड्राउट सिचुएशन में फारमर्स को बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचता है तो फारमर्स को अब 24 घंटा बिजली देने के बारे में आपने क्या कोई कार्य योजना बनाई है ? दूसरी बात यह है कि जो खराब ट्यूबवेल्स हैं, उनकी मरम्मत करने के लिये क्या कोई योजना तैयार की गई है ?

जो नहरें चलती हैं, तो वह रात-दिन चलाई जायेंगी या नहीं, क्योंकि पानी जो झील में है, पानी तो अभी है आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक, तो यह नहरें चलेंगी? मगर जो छोटी-छोटी नहरें हैं, इनमें बहुत घास होता है और उससे पानी बहने में रुकावट होती है । तो क्या उसकी सफाई की जायेगी या नहीं? यदि सफाई करेंगे, तो फार्मर्ज को ज्यादा पानी मिल पायेगा और वाटर मैनेजमेंट के मुताबिक पानी का बचाव भी ज्यादा होगा ।

इसी तरह हमारा जो फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे संपर्क किया है या नहीं ? इस इंस्टीट्यूट के जरिये इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं ?

हमारे देश में ड्राई फार्मिंग भी है, तो ड्राई फार्मिंग इंस्टीट्यूट से संपर्क करके उसके जरिये सूखाग्रस्त एरिया में किस-किस प्रकार की क्राप्स हम कम पानी में पैदा कर सकते हैं, इसके बारे में क्या किया जा रहा है ?

इसके अलावा खास करके मवेशियों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है । तो इस पशुधन को बचाने के लिये फाडर के लिये हमने अभी क्या योजना बनाई है ? जहां ग्रीन एरियाज हैं और जहां फाडर की उपलब्धि ज्यादा है, वहां पशुधन की माइग्रेशन करने के बारे में हमने कुछ सोचा है कि नहीं ?

मुझे लगता है कि जब ड्राऊट सिचुएशन देश में होती है, तब छोटे फार्मर्ज को बहुत हानि पहुंचती है । तो छोटे, मार्जिनल फार्मर्ज को ट्यूबवैल के बारे में, बिजली के बारे में, बीज के बारे में और अभी-अभी जो शुरू-शुरू में बीज बोया गया था, वह तो खराब हो गया है । तो उनको दूसरा बीज दिया जायेगा और वह भी सब्सिडाईज्ड सीड दिया जायेगा या नहीं ?

इसी प्रकार जो फार्मर्स को खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को हमने नये बजट में विदड्रा कर लिया है और इसके मूल्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो क्या इस मूल्य वृद्धि को समाप्त किया जायेगा ?

मान्यवर, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे केवल दो-तीन प्रश्न पूछने हैं । जैसा कि मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल राजस्थान यहां पर जो वर्षा कम हुई, उसका प्रभाव पड़ा है और उसके फलस्वरूप यहां पर सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हुई ।

दूसरा कारण यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो जलाशय हैं, रेजरवायर हैं, उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है ।

तीसरा, यह बतलाया गया है कि मानसून की अनियमित प्रवृत्ति के प्रकाश में कृषि मंत्रालय ने पीने के पानी, चारा और बिजली की आपूर्ति आदि से निबटने हेतु 12 जलाई 1991 को उत्तरी और पश्चिमी राज्यों को पुनः सलाह दी थी । उनसे यह भी अनरोध किया गया कि वे प्रभावित होने वाले संभावित लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए परियोजनाओं के ढांचे तैयार करें ।

तो मैं जानना चाहता हूं कि 12 जुलाई को जो सलाह दी गई थी कृषि मंत्रालय की ओर से, जिन राज्यों के संबंध

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

में सलाह दी गई थी, उनके यहां से भी कोई फीड बैक कृषि मंत्रालय को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ?

विशेषकर टेस्ट वर्क चालू करने के लिए यह राज्यों में क्या योजना शुरू करने जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : कौनसी योजना ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : रोजगार प्रदान करने के लिए टेस्ट वर्क।

इसके साथ ही जो नुकसान हो चुका है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी ? क्या कोई मुआवजा देने का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय की ओर से है ? दूसरा जो यह सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं जहां आलरेडी नुकसान हो चुका है, जहां बुवाई में देरी हुई है तो वहां जो कृषकों के ऊपर लगान की वसूली या हमारे उत्तर प्रदेश में एक पम योजना का टैक्स लगता है, इसको मुआफ करवाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को सलाह दी जाएगी ?

अंत में, मेरा प्रश्न यह है कि जो बजट अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है इसमें उर्वरक के सिलसिले में जो सब-सिडी में कटौती की गई है और उसकी कीमत में 40 प्रतिशत वृद्धि की गई है तो कम से कम यह जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए, यहां दिल्ली की सरकार, जो 40 परसेंट उर्वरकों के दाम में वृद्धि की गई है, उसको समाप्त करेगी ?

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत वक्तव्य सूखे की स्थिति के संबंध में दिया है, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के संबंध में, वैसे तो सभी राज्यों का थोड़ा-बहुत संकेत रूप से उल्लेख किया गया है विशेष रूप से सूखे और वर्षा के संबंध में जो मौसम विज्ञान विभाग है उसका बहुत बड़ा महत्व है, भूमिका है। उस भूमिका के आधार पर अगर सही ढंग से काम हुआ, जो आज का सारा वैज्ञानिक ढांचा है, जिस तरह से जो सारे मिशन चलते हैं तो उसके आधार पर अगर सही समय पर सूचना हो जाए तो बहुत कुछ उस स्थिति और परिस्थिति का मुकाबला पूरे देश के लोग भी कर सकते हैं, किसान भी कर सकते हैं और सरकार की तरफ से पहले से ही कदम उठाए जा सकते हैं। इस सिलसिले में पैरा 2 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 27 मई, 1991 को दक्षिण पश्चिम मौनसून की यह भविष्यवाणी की गई थी कि मौसम में संपूर्ण देश में वर्षा की मात्रा दीर्घवधि औसत महत्व की 94 होगी, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को और भी सक्षम बनाने के लिए जो दूसरे देशों में और भी इस प्रश्न पर इस संबंध में जो विज्ञान आगे बढ़ गया है उसका उपयोग करते हुए क्या उसको आधुनिक बनाने का काम करेंगे ताकि वह पहले से ही, आपने मई को बताया, हो सकता है कि उसके बाद और भी कोई स्थिति आए कि सही जानकारी पूरे देश को, चाहे पानी पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, मौसम किस तरह का होगा, उसके बारे में जानकारी हो सकेगी। दूसरी बात यह है कि यह बात तो आपने अपने उत्तर में दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में, सब जगहों पर कितनी फसल का नुकसान हुआ है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैंने आपने पृष्ठ 3 पर पैरा 8 में लिखा, हरियाणा का जिक्र करने के बाद, कि उत्तर प्रदेश में ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों की फसलों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश में सामान्य चावल क्षेत्र का केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र में ही प्रतिरोपण हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार ने और कृषि विभाग ने माननीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार से इस सूखे के संबंध में कोई रिपोर्ट जरूर मांगी है और उस रिपोर्ट के आने के पश्चात् ही पैरा 3 में उसका उल्लेख भी किया गया है। मेरा स्पष्ट मत है कि क्योंकि हम लोग तो प्राय: घूमते भी हैं और पूरे प्रदेश के लोगों से हमारा संपर्क भी रहता है, यह जो दिया गया है कि

40 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य चावल का प्रतिरोपण हो चुका है और ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों की फसलों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। ज्वार और बाजरा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है हम स्वीकार करते हैं, बुरा प्रभाव से हमारा मतलब यह है कि बिल्कुल ही नष्ट हो गई है। मकई भी हमारे यहां होती है और मकई की फसल 1.19 मिलियन हेक्टेयर में होती है, उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है और जबकि पूरे सूबे की फसल समाप्त हो गई है। चारा भी हमारे यहां काफी है क्योंकि हर प्रदेश में अगर चारा न रहे तो चारे की व्यवस्था करती पड़ती है। लेकिन जब पानी पड़ा ही नहीं है तो चारा मवेशियों के लिए कैसे प्राप्त होगा? उस नुकसान के संबंध में स्टेटमेंट में चर्चा नहीं की गई है। साथ-ही-साथ एक और बहुत ही गंभीर बात की ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट आई है, वह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है बल्कि वास्तविकता के विरुद्ध है। यह क्यों वास्तविकता के विरुद्ध है, उसके कारण में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है कि आगे यदि पानी पड़ जाय तो धान की रोपाई कैसे होगी और दूसरी फसल कैसे बोई जाएगी क्योंकि सीडलिंग्स, जो धान का बीज दिया जाता है, वह तो सारे-का-सारा खेत में समाप्त हो गया। वह तो कुछ है ही नहीं, इसलिए अगर वर्षा होगी, उससे धान की रोपाई हो सकती है, लेकिन अब धान की रोपाई का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उसका बीज ही समाप्त हो गया है। इसलिए मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस संबंध में प्रदेश सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मंगवाने का कष्ट करेंगे क्योंकि सही मायनों में सदन के सामने और प्रदेश की जनता के सामने यह बात आनी चाहिए कि प्रदेश सरकार ने क्यों वास्तविकता के विरुद्ध यह काम किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मांसोदकर) : यादव जी, आपका टाइम खत्म होगया।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, पैरा–7 में दिया है कि केन्द्रीय जल आयोग देश में 56 महत्वपूर्ण जलाशयों को मानीटर करता है फिर भी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय जलाशयों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अब चूंकि आगे यह बहुत ही चिंता का विषय होने वाला है क्योंकि अभी पानी पड़ने के कोई संकेत नहीं हैं कि पानी पड़ ही जाएगा, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जलाशय हैं उनमें जून में क्या स्थिति थी और उन जलाशयों में इस समय पानी के भंडारण की क्या स्थिति है। महोदय, यह चूंकि एक चिंता का विषय हो रहा है, इस बारे में आप विचार करें क्योंकि उससे यह समस्या भी दूर हो सकेगी और आपको भी बल मिल सकेगा प्रदेश सरकार को क्या-क्या निर्देश दिए जाने हैं? साथ ही चूंकि जबकि यह इतना बड़ा मामला हो गया है और प्रदेश सरकारों को आपने निर्देश दिया है तो यह भी रिपोर्ट आपको होगी कि बिजली की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, इनपुट्स की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? इसलिए जबकि केन्द्रीय सरकार उसकी मानीटरिंग करती है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में सूखा हुआ है तो क्या आप उस मानीटरिंग के साथ अपनी ओर से कोई टीम उत्तर प्रदेश में भेजेंगे जोकि वहां अधिकारियों के साथ बैठकर जो नुकसान हुआ है, पूरी उसकी समीक्षा कर सके और समीक्षा करने के बाद केन्द्र सरकार पुनः कोई निर्देश देने का कष्ट करेगी?

महोदय, पैरा–11 में दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो प्राकृतिक आपदा राहत कोष है, उसमें 75 फीसदी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बाकी पैसा राज्य सरकारों का है। इस सिलसिले में मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो कोटा होना चाहिए, वह उसने रखा है या नहीं? अगर रखा है तो उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है? क्या आप उसके उपयोग के बारे में भी अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर वहां से जानकारी मंगाकर सदन की अवगत कराने का काम करेंगे? यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

[श्री रा म नरेश यादव]

महोदय, यह बात भी सही है कि जहां पर सूखा पड़ेगा तो गन्ने की फसल तो सूखेगी ही, कीटाणु लगेंगे ही और ये सारी चीजें होंगी। सारे प्रदेश की गन्ने की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन जो कुछ रह गई है, उसे बचाने के लिए केन्द्र सरकार क्या कोशिश कर रही है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और अगर हमारी फसल का नुकसान होता है, क्षति होती है तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है, क्या कदम उठाने जा रहे हैं? इस संबंध में भी माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to ask the hon'ble Minister certain questions with regard to his statement which he has made in this House and which is, no doubt, a detailed statement and a painstaking statement and it is made after elaborate consideration of the situation resulting from near-failure of monsoon in the country. But certain question remain to be asked with a view to move the hon'ble Minister to consider certain aspects of the matter. Firstly, it is submitted that in the entire statement it appears that the hon'ble Minister's attention has not beed drawn to the conditions prevalent in the State of Jammu and Kashmir. In the State of Jammu and Kashmir the entire Jammu division is fed by monsoon just as Punjab, Uttar Pradesh or Bihar. But monsoon has failed. The result is that in all the *kandy* area of Jammu region the crops have failed. There is no fodder. There is near-famine condition. I would, therefore, request the hon'ble Minister to apply his mind to that side of the country as well and to take steps so that the lot of the people can be ameliorated. In Kashmir the areas which are lying on height such as *kandy* area are also fed by rain water. These are barami lands. *Barami* needs rain, but rain has not come. So, the people living there such as Nomads, Gujjars and Gaddis are suffering for want of all these and the hon'ble Minister will do well in these bad days through which we are passing to see that the difficulties of the people are removed and turn his kind attention to those who are suffering from possible famine.

Secondly, I would like to request the hon'ble Minister to find out whether any programme such as food-for-work programme can be undertaken in areas where he finds that as a result of this natural calamity the crop has failed. The hon'ble Minister may kindly see what the foodgrains available are with the Food Corporation of India and that is an enterprise which has got ample foodgrains with it and, I think, the hon'ble Minister can tap that Corporation for the purpose of ameliorating the condition of the people who are affected by the failure of rain. For that reason the food-for-work programme may be undertaken, that is to say whatever works are to be done in those areas may be got done by the people and they may be paid in return for their work in foodgrains.

Last but not the least, the hon'ble Minister has said in para-10 that as early as in April 1991 the Ministry of Agriculture had written to the State Agriculture Production Commissioners suggesting Model Contingency Crop Plans to meet the adverse situation. That means the Central Government had risen to the occasion well in time. But I would like the hon'ble Minister to make us aware what the reaction was of the States which were approached and which were told that they should evolve Model Contingency Crop Plans to meet such a situation as and when it arose. With these words I thank the hon'ble Minister for making this statement and I hope he will consider our lot also.

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी से जैसे बयान की आशा थी वैसा वह नहीं है। वह मंत्री भी हैं, लेकिन इससे पहले किसान नेता हैं और उनके बयान में मुझे कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, मुझ क्षमा करेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक ही बात अपने जिले के बारे में कहूंगा। मेरठ जनपद में, जहां मंत्रीजी गए भी हैं, एक क्षेत्र है चौगावा, यह बिनोली विकासखंड में पड़ता है, वहां पर सामान्यतः जो वाटर लेवल है 60 फीट का है और अब जब सूखा पड़ रहा है पानी का नाम नहीं है तो वाटर लेवल और नीचे चला गया है। यहां तक कि जो बड़े सरकारी ट्यूबवेल हैं, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है, नहर वहां बिल्कुल नहीं है और ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा, प्राइवेट नहीं सरकारी मैं कह रहा हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि प्रादेशिक सरकार क्या कर रही है, एक तो यह रिपोर्ट आप मंगायें? और श्रीमान्, अगर वह कुछ नहीं कर रही है या काम कर रही है या पैसे की कमी है—यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़े मेहनती किसानों का है और इसमें कम से कम 50 गांव हैं, इस क्षेत्र में कम से कम पानी की व्यवस्था नहर की या और किसी किस्म के ट्यूबवेल की, मैं नहीं जानता कि जहां इतना गहरा पानी हो वहां कोई और टैक्नीक हो सकती है, ऐसी कोई व्यवस्था राज्य सरकार से मिलकर आप अपने स्तर पर करा सकेंगे? यह बड़े संतोष की बात होगी वहां के लोगों के लिए और देश के लिए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सूखे में किसान की क्या हालत है, यह आपकी रिपोर्ट में नहीं है। मैं कहता हूं कि त्राहि-त्राहि मची हुई है और आपने जो फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ाए हैं उसने किसानों की कमर और तोड़ दी है। तो क्या किसान को राहत देने के लिए गन्ने का भाव जो आप तय करेंगे, जिस पर आप विचार कर रहे होंगे, क्या गन्ने का भाव, सूखे की वजह से राहत देने के लिए, 50 रुपए प्रति क्विंटल तय करने के लिए आप विचार करेंगे? यह आप स्पष्ट करें, साफ, साफ। आप किसान हैं।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से दो चार बातें पूछना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, हमारे देश की बड़ी बदकिस्मती है कि हमें आजाद हुए 44 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक हमारी कोई नेशनल पालिसी इस बारे में नहीं बनी है। दो दिन पहले भारत सरकार के मंत्री ने फ्लड के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि फ्लड की वजह से इतने किसानों का नुकसान हो गया और कल कृषि मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि सूखे की वजह से इतना नुकसान हो गया। मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या कोई ऐसा इंतजाम सरकार नहीं कर सकती कि जो ज्यादा पानी से नकसान होता है, जो फ्लड का पानी होता है, क्या उसको कंट्रोल करके, उसको स्टोर करके, जहां पर सूखा पड़ता है, उस पानी का इस्तेमाल उस इलाके में किया जाए ताकि जो बाढ़ से नकसान होता है वह भी न हो और जो सूखे से नकसान होता है वह भी न हो? मैं समझता हूं कि सरकार के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं है और कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी या कमीशन ऐसा बनाना चाहिए। कहीं पर कावेरी नदी का झगड़ा हो रहा है, कहीं पर हमारे हरियाणा के अंदर जो पाकिस्तान से पानी खरीदा गया था हरियाणा और राजस्थान की जमीन को इरिगेट करने के लिए, वहां पर एस०वाई एल० कैनाल करोड़ों रुपए लगाकर हरियाणा में बनी पड़ी है लेकिन जो लिंक कैनाल पंजाब में बननी है, वह नहीं बनी और जो पानी हमने पाकिस्तान से मोल लिया वह न हरियाणा की जमीन में लग रहा है, न राजस्थान की जमीन में लग रहा है और वह बेकार हो रहा है और फिर पाकिस्तान में जा रहा है, सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। हमारे हरियाणा में, मंत्री महोदय ने पैरा 9 में लिखा है कि सिर्फ दो जिले इफेक्टिड हुए हैं, लेकिन चेयरमन साहब, सारा हरियाणा इफेक्टिड है। आज वहां पर इतना सूखा है कि सारी फसल सूख चुकी है। हम वहां पर चावल पैदा करते हैं जो एक्सपोर्ट होता है, फारेन एक्सचेंज कमा कर लाया जाता है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। न वहां पर बिजली दी जा रही है, न वहां पर पानी दिया जा रहा है और मैं आपके माध्यम से यह मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो टेम्परेरी राइस शूट्स हरियाणा में दिए

[श्री महेन्द्र सिंह लाठर]

जाते थे चावल पैदा करने के लिए, इस दफा हरियाणा की सरकार ने वह टेम्परेरी राइस शूट्स नहीं दिए। तीसरे दिन बिजली दी जा रही है, मोटरें सड़ रही हैं, सब-सायल वाटर लेवल नीचे चला गया है। अगर 5 हर्स पावर की मोटर से वह नहीं उठता और वहां पर कोई किसान अगर 8 हर्स पावर की मोटर लगाता है पानी उठाने के लिए तो उसका वहां पर चालान किया जाता है, पांच-पांच हजार रुपए का जर्माना किया जाता है।

मैं एक बात और मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किसान ने बीज भी डाल दिया, किसान ने खाद भी डाल दी, किसान ने मजदूरी भी लगा दी लेकिन वह फसल सूख चुकी है सूखे की वजह से। क्या भारत सरकार इन किसानों को कोई कम्पनसेशन देने की बात करेगी जिनकी फसल को नकसान हो चुका है?

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, my first question is whether the Centre has sent any Central team for *assessing* to the draught-affected areas. The second question is whether there was any Central assistance in the form of interim relief to any State. The third is whether there are any starvation deaths in any State. My fourth question is this in the coming days, there are going to be drinking water problem, cattle fodder problem, unemployment problem, etc., in the rural areas. The statement is totally evasive. It has thrown the entire burden on the States. I would like to know from the Minister whether the Central Government has started any anti-drought schemes and allotted any money to the Department of Rural Development to help the States. Before and during the Gulf War, ecologists, scientists and environmentalists predicted that there would be some impact on the monsoons in India. I would like to know whether there is any such impact on India. I come to my last question. The World-Watch Institute based in Washington has, in its report said that India will be facing famine conditions in the nineties. It also stated that this is because of gross mismanagement, deforestation, denuding of trees and water-tables going down, etc. Has the Government gone through this report? These are the questions on which I seek the Minister's clarifications.

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष जी, आजादी के 44 साल बाद भी—अल्लाह मेघ दे, पानी दे, वृष्टि दे, ऐसा हमारे मंत्री जी के बयान से पता चला कि अगर बारिश ठीक हो गई तो सब ठीक है वरना हम परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वह यह है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ता है, वह यह है कि बड़े-बड़े हमारे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, वर्षों से वे पेंडिंग रहते हैं—क्लियरेंस नहीं, फंड एलोटमेंट नहीं, उस मामले में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही खुद जरा कोशिश करके जैसे बहुत से स्टेट से यह मांग उठती रहती है, तो हमारे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके लिए कोशिश एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कर रही है या नहीं?

दूसरा है कि स्माल एंड मीडियम, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। उस मामले में भी जो स्टेट में है, बहुत से स्टेट में यह काम करके सूखा का जो असर है उसको टाला जा सका है। मैं बंगाल से आया हूं। मैं कह सकता हूं। अभी हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे, कि वर्षा का पानी को स्टोर करके बाद में उसको सूखा मौसम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्षों से ऐसे बहुत से टैंक हैं जिनको नार्थ इंडिया में भी कई जगहों पर हम लोग देखते हैं, जिसमें वर्षों से सिल्ट जम गये हैं अतः उसको डिसिल्टिंग करके वहां पानी स्टोर करने का बंदोबस्त किया जाये और जहां नहीं हैं वहां यह ग्रामीण कर्मसंस्थान योजना के द्वारा जसे जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुछ एम्पलायमेंट का बंदोबस्त गांवों में किया जा रहा है, तो उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं ताकि गांव के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें लगा कर

सूखा मौसम में बड़े-बड़े टैंक खोद सकते हैं ताकि बाद में उसमें हम मानसून में पानी स्टोर कर सकते हैं ।

जैसा स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो खेती का काम है वह बहुत कम हुआ है। तो इसके लिये किसानों का जो मामला है उसको नजर दिया जायेगा, ऐसा मंत्री जी ने बताया और उसमें एश्योरेंस भी दिया है। लेकिन जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं जिनको इस सूखा मौसम में कोई काम मिल नहीं रहा है, क्योंकि खेत में कोई काम मिल नहीं रहा है- क्योंकि खेत में काम ही नहीं तो क्या उसके लिए कोई विशेष प्रबंध किया जा सकता है, यह मंत्री महोदय जरा बतायेंगे ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारा प्रदेश सूखे से बुरी तरह ग्रस्त है । महोदय, पहले जहां पर किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते थे, वहां उत्तर प्रदेश सरकार बी.डी.ओ. के माध्यम से फ्री बोरिंग कराती थी और नलकूप के लिए डीजल इंजन हेतु पैसा उपलब्ध कराती थी, कर्ज के रूप में, जो बैंकों से दिया जाता था । महोदय, कुछ समय से, मेरे ख्याल से पिछले एक माह या दो माह से यह लोन की व्यवस्था और बोरिंग की व्यवस्था बिल्कुल बंद हो गई है, जब कि सूखे से किसानों की हालत इतनी खराब हो रही है । महोदय, इस तरह किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है । तो मैं चाहूंगी कि इस व्यवस्था को दोबारा शुरू कराया जाए ।

महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि केन्द्रीय जल आयोग 56 जलाशयों का मानिटरिंग करता है । मैं जानना चाहूंगी कि क्या प्रदेश सरकारें संकटकालीन व्यवस्था के लिए कुछ जलाशयों की मानिटरिंग करके किसानों को ऐसे वक्त में पानी उपलब्ध कराने का काम नहीं कर सकती हैं ?

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के पैरा 8 में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल 40 प्रतिशत धान का प्रतिरोपण हुआ है । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मंत्री जी का यह बयान गलत है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि फिर से इसका सर्वेक्षण करवा जाए । हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम जानते हैं कि वहां 10 प्रतिशत भी धान की रोपाई नहीं हुई है और खरीफ की जो फसलें हैं ज्वार, बाजरा, ये तो बिल्कुल जल गई हैं। तो मे माननीय मंत्री जी से यह बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और स्वयं सरकार की ओर से कल लोकसभा में यह स्वीकार किया गया कि देश में 23,76,70,000 लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं। तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सूखा राहत के लिए कितना धन सरकार की ओर से आवंटित किया गया है ?

महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार सस्ते गल्ले की दुकान खोलने के लिए क्या प्रावधान कर रही है ? मे मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के बारे में मानिटरिंग करायें क्योंकि वहां की सरकार जो है उसको तो सूखे का ज्ञान नहीं है। वह तो राम मंदिर बनवाने के चक्कर में हैं। किसानों से उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में जो भयंकर सूखा पड़ा है, उसकी मानिटरिंग कराएगी ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir. I will put only pointed questions.

Sir, it has been admitted by the honourable Minister of Agriculture that

[Shri V. Narayanasamy]

the monsoon has not actually reached Delhi and other places in the northern part of the country and there has not been sufficient rainfall in this region. Sir, the Minister has much experience so far as agriculture is concerned and he may be knowing one thing. Whenever there is a heavy downpour, the water goes into the sea. By digging bore wells the water can be stored in the underground so that it can be used for irrigation purposes by the farmers. We can use that water by retapping it. This system which was introduced has not been implemented in many States. I would like to know what is being done in this regard.

Secondly, the loss of crops due to the drought conditions prevailing in the western part of the country has not been assessed and the statement does not say anything about it. I would like to know what the actual loss is and also loss in terms of money. I would like to know what the estimate is in this regard.

Thirdly, there has been pre-monsoon showers in some areas in Tamil Nadu and in my area, Pondicherry. But, in the southern part of Tamil Nadu, this has not taken place. I would like to know whether the Central Team visited the drought-affected areas and assessed the situation there in order to help the States concerned. I would like to have clarifications on these points. Thank you, Sir.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : फिर एक सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखा जबरदस्त है। कुएं भी सूख गए हैं, जमीन भी सूख गई है। खाने के साथ पानी भी सूख गया है। शायद आपके ध्यान में होगा कि जब इस तरह का सूखा सन् 1980 में आया तो अन्न के बदले काम की योजना चलाई गई थी। उससे लोगों का इतना पेट भरा था कि जितना भरे मौसम में भी नहीं भरा।

श्री राम नरेश यादव : जरा करेक्ट कर लीजिए। यह 1977 में हुआ था।

श्री अनन्त राम जायसवाल : रामनरेश जी उस समय मुख्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उस वक्त लोगों का इतना पेट भरा था कि रेकार्ड यह बतला रहे हैं कि लोगों की तंदुरस्ती में भी सुधार हुआ था। उस योजना को चलाने में क्या भारत सरकार को कोई आपत्ति है? अगर नहीं है तो क्या उसको तुरन्त लागू किया जाएगा?

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, with your kind permission I want to ask one question. There is a difference in giving the Central assistance in the case of floods and drought. Whenever we ask the question, the Ministry says that these are the norms fixed by the Finance Commission. So, I request the hon. Minister to move the Finance Commission that both are natural calamities and in.....

SHRI V. NARAYANASAMY: Drought is more serious.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: .... getting the Central assistance, floods and drought should not be discriminated. The norms of assistance should be changed. So, I request the Minister to move the Finance Commission highlighting the calamities as well as the sufferings of the people in the case of floods as well as drought and find an equitable solution for both.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have a dynamic Minister. He will do everything.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Everytime the Ministry answers that these are the norms fixed by the Finance Commission. Actually, the Ministry has to move the Finance Commission.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Sir, I support Mr. Hanumanthappa.

श्री बलराम जाखड़ : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्यों के जो प्रश्न हैं, वह तकरीबन सारे के सारे उत्तर मैंने

दे दिए हैं। कुछ थोड़े से सवाल उत्पन्न होते हैं, उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगा जैसे बिहार के मुतालिक माननीय सदस्या ने कहा सोन कैनाल के बारे में। मैं आपकी बात को इरिगेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचा दूंगा लेकिन यह ज्यादा काम स्टेट सरकार का है। प्रदेश सरकार अगर चाहे और उसे चाहिए और डिसिल्टिंग कैनाल की करनी चाहिए।

श्रीमती कमला सिंहा : डिसिल्टिंग की बात नहीं है। यह तीन प्रांतों की बात है। सोन सिस्टम से पानी रिलीज करने की बात है।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने कहा कि इरिगेशन मिनिस्ट्री तक आपकी बात को पहुंचा दूंगा, वह देख लेंगे।

जहां तक आपने पूछा कि डीजल और पावर नहीं है। बात सही है कि पावर के बगैर कोई काम बनता नहीं है। देश की प्रगति करनी है तो पावर की बहुत आवश्यकता है। विशेषकर आपके प्रान्त में मैंने देखा कि बिजली का उत्पादन बहुत कम है। सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए और यहां से भी मैं ऊर्जा मंत्री जी के साथ बात करूंगा कि उनके साथ कोआर्डिनेट करें जिससे उत्पादन बढ़ सके। जितना उत्पादन अधिक होगा उतनी ही उत्पत्ति भी अधिक होगी चाहे धान की हो, चाहे इंडस्ट्री की हो।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुतल्लिक आपने कहा, और साथियों ने भी कहा। मैंरे पास अभी रिपोर्ट आई है प्रदेश सरकार की। उसमें उन्होंने लिखा है :

> "According to the latest rainfall figures received from the Meteorological Office, Amausi, only 7 districts—Jhansi, Allahabad, Lalitpur, Muzaffarnagar, Meerut, Eta and Badau—have received almost normal rainfall. Even in these districts the rainfall has not been evenly distributed. Eight districts of the State have received 60 to 80 per cent of the normal rainfall. Another 10 districts are in the category of highly deficient as they received only 40 to 60 per cent of the normal rainfall. The position is very critical in the remaining 38 districts of the State where only scantly rain, below 40 per cent of the normal has been received."

जो आपने 40 परसेंट के मुतल्लिक बात की थी उसमें इन्होंने कहा है कि 36 परसेंट एरिया ही है। लेकिन जैसा आपने कहा है मीटिंग करनी चाहिये...

श्री राम नरेश यादव : अभी जो रिपोर्ट आयी है वह भी सही नहीं है। 64 जिलों में कम से कम 50 जिले ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है।

श्री बलराम जाखड़ : जो आपने मीटिंग का सुझाव दिया था वह हमने 5 तारीख को रखी है। बिहार और वे सभी सूखाग्रस्त जो प्रदेश हैं उनकी मीटिंग यहां हो रही है। उसमें बातचीत करके हम देखेंगे।

दूसरे जो 24 घंटे सप्लाई का प्रश्न है वह तो स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से है। उनको हम कहते रहते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा बिजली दें और जहां सूखा हो तो फसल बचाने के लिये इंडस्ट्रीज की बिजली काट कर इनको दी जाय। इसी के साथ कैनाल सिल्ट क्लीयरेंस की बात है इसको स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिये। ये छोट-छोटे काम हैं इनको प्रदेश सरकार कर सकती है और करने चाहियें। हम उनको लिखेंगे। मेरे ख्याल में जो आपके अपने प्रदेश के एम0एल0एज0 हैं उनसे हम को संपर्क करना चाहिये ताकि वे अपनी सरकार को कसते रहें। यह काम गंभीरता से होना चाहिये।

आपने मौसम विभाग के बारे में कहा था। यह बिल्कुल ठीक है कि प्रगति हर क्षेत्र में हो। वैसे मौसम विभाग पहले से काफी अच्छा है। अब तक

[श्री बलराम जाखड़]

तकरीबन तकरीबन जो भविष्यवाणी की हुई है वह ठीक-ठीक चल रही है। काफी हमारे पास साधन हैं जिससे हम जान सकते हैं कि क्या-क्या कब-कब हो रहा है। उसके जानने से फायदा पहुंचता है और उसके बाद उसकी तैयारी की जाती है। इसलिये हमने मई के महीने में बुलाकर बात की थी कि आप आइये, हम से बात करिये कि किस तरह से हम इसका निराकरण कर सकते हैं, आने वाली विपत्ति कैसे ठीक हो सकती है।

कम्पनसेशन की बात की थी। सर्वे टीम भेजने की बात काफी मैंने सदस्यों ने की कि आप अपनी सर्वे टीम भेजिये। वह देख कर काम करें कि किस प्रकार से नुकसान हुआ है और उसका क्या करना चाहिये। इसके मुतल्लिक अगर आपने मेरा बयान ध्यान से पढ़ा होता तो यह दिक्कत नहीं आती। इसमें हमारी कुछ बदिश आ गई है। पहले तो सर्वे टीम सेंटर की तरफ से भेजते थे जब भी कोई ऐसी कलेमिटी हो जाती थी नेचुरल प्राकृतिक विपत्ति आ जाती थी तो यहां से टीम जाती थी। देखते थे, सर्वे करते थे और फिर आपस में बात-चीत होती थी, अनुदान यहां से जाता था। लेकिन मुसीबत लोगों को महसूस हुई और स्टेट गवर्नमेंट ने इस के लिये आपत्ति उठाई। यह कहा कि पैसा हमारा है यह चौधरी क्यों बन बैठे। हमारा पैसा हमें ही दे दो। नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में लिखा है।

"The primary responsibility of managing natural calamities is that of the State Governments. Emphasizing this principle, the IX Finance Commission recommended ready access to resources and autonomy in relief operations for the States. On the recommendations of the IX Finance Commission, from 1st April 1990, a Calamity Relief Fund (CRF) for financing relief expenditure has been constituted for each State, 75 per cent of which is contributed by the Central Government and the balance by the State Government concerned. An annual contribution of Rs. 804 crores for the State CRPFs has been envisaged for, and of this amount Rs. 603 crores are contributed by the Central Government. Fifty per cent of the Central share of the CRF for the year 1991-92 has already been released to States. The State level Committee, headed by the Chief Secretary of the State, is empowered to decide on all matters connected with the financing of the relief expenditure, including norms of assistance. The State Governments are required to meet all expenditure on relief operations from the CRF."

और कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अगर वह हमसे पहले भी मांगते हैं कि हमें एक किश्त रिलीज कर दो तो हमने दो किश्ते रिलीज की हैं। यू०पी० का उदाहरण देता हूं। आपने मुझ से पूछा है...

श्री राम नरेश यादव : जो रिलीफ वर्क है वह तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी लेकिन सचमुच कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में तो आप करा सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : वह हमारे पास नहीं रखा। टीम हम सर्वे की तभी भेजते जब हमारे पास होता। मैं आपको बताऊं पिछले साल हमने 90 करोड़ रुपया यू०पी० को देना था। उसमें से 28 92 करोड़, 29 करोड़ समझ लीजिये यू०पी० ने खर्च किया है। उसमें से 60 करोड़ रुपय बचा हुआ है। 90 करोड़ इस साल का है तो अभी उनके पास 150 करोड़ रुपये बचा है जिसको वे खर्च कर सकते हैं अगर कोई नेशनल कलेमिटी आती है तो।

श्री ईश दत्त यादव : इस साल कितना दिया ?

श्री बलराम जाखड़ : हमारे पास जितना रिजर्व होता है किश्तों में दे देते

हैं । हमने दो किश्ते रिलीज कर दी हैं यानी 50 परसेंट रिलीज कर दिया है। और अगर आवश्यकता हो तो वे हमसे और किश्तें भी मांग सकते हैं और हम अगले साल की किस्त भी दे सकते हैं। ऐसी कोई डिमांड हो जाय, ऐसी कोई विपत्ति आ जाय जिसको सभाला नहीं जा सकता है तो सहायता दी जा सकती है। कोई नेशनल कलेमिटी, राष्ट्रीय किस्म की विपत्ति घोषित हो जाय उसके लिये सेंटर एक टीम भेज सकता है। यह एक नई चीज है और उसमें आपस में बात हो सकती है।

आपने जम्मू-कश्मीर की बात की है। उसको इसमें रखा नहीं गया है। जम्मू-काश्मीर भी एक डेफिसिट एरिया है। वहां बरसात नहीं हुई है। उसकी भी हमें चिंता है। खाने-पीने के मुत्तलिक आप चिंता न कीजिये। भगवान की कृपा से हमारे पास पूर्ण भंडार है और हमारे पास 19 मिलियन टन का अनाज है। उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप जितना भी कहेंगे उसको हम पूरा कर देंगे। मेरे पास आंकड़े हैं। इसमें कुछ विरोधाभास है। यू. पी. का 20.60 परसेंट धान का रोपण हुआ है। पिछले साल नार्मल 51 परसेंट था और लास्ट ईयर 41 परसेंट था। मेज का 50.9 परसेंट है और नार्मल 11.32 था। लास्ट ईयर 6.81 परसेंट था और बाजरे का 1.17 परसेंट है और नार्मल 8.33 है। लास्ट ईयर 2.50 था। बिहार में शोइंग 11.37 है और पहले यह 51 परसेंट था और लास्ट ईयर 36 परसेंट था। मेज का 40.52 परसेंट था और नार्मल 60.84 परसेंट है और पिछले साल 5.5 परसेंट था। बाजरे का 1.95 परसेंट है और नार्मल 2.5 परसेंट है और पिछले साल 2.25 था। इस प्रकार से सारी बातें हैं। एक माननीय सदस्य ने रिजरवोयर्स के बारे में पूछा।

श्री महेन्द्र सिंह लाटर : बाढ़ के बारे में क्या कोई नेशनल पालिसी भी है?

श्री बलराम जाखड़ : यह मसला इरीगेशन डिपार्टमेंट के पास है। वैसे तो मेरे दिमाग में ये चीजें जुड़ी रहती हैं और मैं इस संबंध में काम भी करता रहता हूं। मैं इस संबंध में बता सकता हूं। लेकिन करना उनको ही है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जल्दी क्यों नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी होना चाहिये। जितनी देर होती है उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ जाता है और नुकसान भी होता है। इसलिये सोचना पड़ता है। आप जानते हैं कि जितना कपड़ा होता है, कोट भी उसी हिसाब से बनता है। असल मसला फाइनेंस का है। उनका गेस्टेशन पीरियड लंबा होत है। आपने कहा कि पाकिस्तान में पानी जा रहा है। हम थाई डैम बना रहे हैं। पोंग और भाखड़ा डेम हमने बनाये हैं। मैं उस समय सिंचाई मंत्री था। मेरी देखरेख में पौंग डेम बना। उसमें कितना टाइम लगता है और उत्पादन कितना होता है, यह मैं जानता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह लाटर : एस० वाई० कैनाल के बारे में क्या स्थिति है?

श्री बलराम जाखड़ : एस० वाई० केनाल का मेरे साथ संबंध नहीं है। वह दूसरा महकमा है और वही इस बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार से माननीय सदस्यों ने जितने भी सुझाव दिये हैं मैं उनका ध्यान रखूंगा।

श्री छोटू भाई पटेल : 40 परसेंट फर्टिलाजर में जो सबसीडी है उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़ : इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। सारी बात चल रही है, क्या होगा और क्या नहीं होगा, सारी आगे-पीछे की बातें देखनी पड़ती हैं। देश के हित में क्या है और किसानों के हित में क्या है, यह देखना पड़ता है। किसानों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता कि अगर हम किसानों का ध्यान नहीं करेंगे तो देश का ध्यान कौन करेगा। देश को अगर सम्मान, आत्मविश्वास और आत्म-

[श्री बलराय जाखड़]

निर्भरता दी है तो वह किसान ने दी है। जब हम 34 करोड़ थे तो लाखों टन अनाज बाहर से मंगाया जाता था और आज हम 85 करोड़ हो गये हैं, तो भी आत्म निर्भर हैं। यह किसान की देन है। इस समय जो कुछ किया जा रहा है वह किसी विपत्ति के आधार पर किया जा रहा है। हम सोच रहे हैं और उसका निराकरण आप और हम मिलकर करेंगे तभी बात बनेगी।

श्रीमती कमला सिंहा : मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अभी बिजली का उत्पादन दो-चार दिन में तो हो नहीं सकता है। इसलिए सोन सिस्टम से, सिंगरौली से और उत्तर प्रदेश से क्या 1500 मैगावाट बिजली बिहार को दी जाएगी ?

श्री बलराम जाखड़ : इस बारे में तो ऊर्जा मंत्री बता सकते हैं। मैं अनाधिकार चेष्टा करूंगा तो वह अच्छा नहीं लगता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप ऊर्जा मंत्री तक इस बात को पहुंचा दीजिये।

श्री बलराम जाखड़ : वह भी पहुंचा दूंगा।

श्रीमती कमला सिंहा : इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए आप ऊर्जा मंत्री को कह तो सकते हैं कि वह तुरंत कार्रवाई करें।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपकी बात को उन तक पहुंचा दूंगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास इतने साधन हैं और अगर आप चेष्टा करें, अगर हममें भावना बढ जाय काम करने की, दत्तचित्त होकर, देशभक्ति के साथ अगर काम किया जाय तो बिहार एक ऐसा प्रांत है जो सब को अनाज दे सकता है, यह मेरी धारणा है। मैं बार बार वहां गया हूं, मैंने देखा है, जमीन के साथ मेरा लगाव है, मैं जानता हूं कि कैसे किया जा सकता है। सिर्फ करने की हिम्मत हो। आप सारे लोग बैठें। अगर नक्शा बदलना है तो प्रारूप बदल जायेगा और वहां एक नई बहार आ जायेगी।

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कमला सिन्हा जी ने जो कहा उनको मैं जरा दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि रिहंद डाम से बिजली चली जाती है बंबई को और वहां से चली जाती है पंजाब को...

श्री बलराम जाखड़ : रामअवधेश जी इससे मेरा संबंध नहीं है।

श्री राम अवधेश सिंह : गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पांसबिलिटी होती है, हम इस बात को मानते हैं। इसलिये आप हमारी इस बात को पहुंचा दें जो बिहार को सूखे के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।... (व्यवधान)..

श्री बलराम जाखड़ : आप कहें कि गाड़ी से बंबई जाना है और कलकत्ता चले जांय, इससे बात तो नहीं बनेगी। अगर आप सजेशन देंगे तो हम आपकी बात को वहां तक पहुंचा देंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : पंजाब को बिजली जायेगी और हमारे पानी से वह बिजली बनेगी लेकिन हमको वह बिजली नहीं मिलेगी, इससे बढकर घोर अन्याय क्या होगा ?

श्री बलराम जाखड़ : देश में पैदा होने वाली सारी बिजली और यह सारा देश आपका है और इसका वितरण आपकी ही सरकार और आप ही करते हैं। कभी आप होते हैं और कभी और होता है। (व्यवधान) इस धारणा से यह देश अवन्नति कर रहा है कि यह मेरा है। यह मेरा नहीं बल्कि हमारा सब का है। हमें इस भावना को जाग्रत करना है कि यह हमारा देश है। कोई पंजाबी हिन्दुस्तानी नहीं बनना चाहता यह क्या तमाशा है।... (व्यवधान)..

शांति त्यागी जी ने कहा कि पानी नीचे चला गया है। तो इसके लिये भी यही है कि वहां की सरकार को हम लिख सकते हैं। 5 तारीख को वे लोग आ रहे हैं। आप इस बारे में अगर थोड़ा सा आवेदन लिखकर देंगे तो मैं उनको वह दे दूंगा क्योंकि यह मामला प्रदेश सरकारों के अन्तर्गत आता है।

अगर हम बीच में पड़ेंगे तो वे कहेंगे कि अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं और सेंटर हमारे मामलों में दखल दे रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच आपस में सामंजस्य पैदा हो और आपस में मिलकर, सहकारिता के आधार पर हम काम करें।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : गन्ने के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री बलराम जाखड़ : गन्ने का बता रहा हूं वह रुरल डवलपमेंट में आयगा। मैं उनको बता दूंगा, रुरल डेवलपमेंट के बारे में, जवाहर योजना के मुत्तलिक जो है, वैसे ही उस के मुत्तालिक बात है। गन्ने का, अनाज का, सारी बात जो मैंने बताई वह मैं बता दूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि मैं किसान के हितों के लिये दत्तचित्त हूं। मैंने सारी जिंदगी इसमें खर्च कर दी। न मुझे व्यापार आता है और न कुछ किया है। मैंने खेती की है, खुरपा चलाया है और अन्न का उत्पादन किया है, बूटे लगाये हैं। . . (व्यवधान) . . वह भी मेरे दिमाग में है लेकिन हो सकता है कि दृष्टिकोण में अंतर हो। लेकिन मैं किसान को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाना चाहता हूं। मैंने यह बात वित्त मंत्री से की है और वित्त मंत्री को सदन में यह दो बार कहलवाया है कि किसानों की हितों की रक्षा की जायेगी। जिस भी तरह हो उसके हितों की रक्षा की ही जानी चाहिये क्योंकि मैं यह मानता हूं कि किसानों के बगैर हमारा देश नहीं चल सकता है, हम चल नहीं सकते।

तो मैं आपसे कह रहा था कि शुगर का ही नहीं, अनाज का भी, कपास का भी, सारा कुछ जो है मेरे पास उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसको हम देख रहे हैं कि किस तरह हमको किसान का घर पूरा करना है, उसके लिये भी करना है और जिनके पास नहीं है उनका घर भी कैसे पूरा करना है, तो सारी बातें हमारे विचाराधीन हैं। आपके हितों की रक्षा के लिये मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The House is adjourned till 11 a.m. on Monday, the 5th August.

The House then adjourned at twenty-five minutes past six of the clock till evelen of the clock on Monday the 5th August 1991.